डीजीपी बनने की रेस में आया नया मोड़

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

गतांक में **'डीजीपी बनने की रेस में तीन आगे'** शीर्षक से प्रकाशित होने वाले समाचार में बताया गया था कि डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल 15 अगस्त को रिटायर होंगे। लेकिन खबर छपते-छपते ही उनकी रिटायरमेंट तिथि 31 जुलाई कर दी गई थी।

मनोज यादव, आईपीएस

समाचार प्रकाशित होने के तुरन्त बाद चयन प्रकिया में एक बड़ा मोड़ आ गया। हरियाणा सरकार ने अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार जिन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे थे, उसमें वरिष्ठतम अधिकारी मनोज यादव का नाम नहीं भेजा गया था। बहाना यह लगाया गया था कि वे इस पद पर आने के इच्छुक नहीं हैं। **'मज़दूर मोर्चा'** ने गतांक में ही लिख दिया था कि ये बहाना चलने वाला नहीं है और वही हुआ भी। अब यूपीएससी ने मनोज यादव का नाम पैनल में डालकर भेजने का आदेश हरियाणा सरकार को दिया है।

मनोज यादव का नाम पैनल में जाने से शत्रुजीत कपूर का नाम तीसरे नम्बर से खिसक कर चौथे नम्बर पर चला जायेगा। हरियाणा सरकार को यूपीएससी पैनल में शामिल 3 नामों में से किसी भी एक को चुनने का अधिकार तो है लेकिन उसे ऊपर के नामों को रद्द करने के उचित कारण बताने होंगे।

अब यूपीएससी से जो पैनल आयेगा उसमें पहले नम्बर पर मनोज यादव होंगे। उनके द्वारा इस पद को अस्वीकार करने की सूरत में मोहम्मद अकील व आरसी मिश्रा बचते हैं। चौथे नम्बर पर आने वाले शत्रुजीत कपूर को चुनने के लिये उक्त नामों में से किसी को काट पाना सम्भव नहीं दिखता। जाहिर है ऐसे में मुकाबला अकील व मिश्रा के बीच ही होने वाला है।

बेशक यूपीएससी द्वारा मनोज यादव का नाम मांगा जाना विधि सम्मत है, लेकिन फिर भी चर्चा यह है कि इसके पीछे आईएएस अथवा संघ लॉबी का हाथ है। जो भी हो यह स्थिति कपूर के लिये तो घातक सिद्ध होने वाली प्रतीत होती है। मनोज यादव, जब वे हरियाणा में जाना ही नहीं चाहते और उनकी तैनाती बतौर डीजीपी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो चुकी है तो उनका नाम पैनल में क्यों घसीटा जा रहा है? मनोज से लेकर कपूर तक, इन चारों अफ़सरों के लिये डीजी बनने का यह आख़िरी मौका है, जो बन गया वह बाकी तीनों को रिटायर करके जाएगा।

इस पूरे विवाद में गौरतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्देश का हवाला देकर यूपीएससी मनोज यादव का नाम पैनल में डलवाना चाहती है, वह नागालैंड के डीजीपी नियुक्ति के मामले में दिया गया था।

क्योंकि यह निर्देश एक विशेष मामले तक सीमित था और सुप्रीम कोर्ट के इस विषय पर आये ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा नहीं था, लिहाजा इसे हरियाणा के मामले में लागू करना संदेह पैदा करता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष एक संघी पृष्ठभूमि का व्यक्ति है और वह राजनीतिक निर्देशों के अनुसार पैनल भेजेगा। अब यह मुख्यमंत्री खट्टर पर निर्भर है कि वे अपने चहेते शत्रुजीत कपूर का नाम पैनल में डलवा पाते हैं या नहीं।

लावारिस कुत्तों के नाम पर लूट कमाई का ठेका इस बार नई कंपनी को

नगर निगम ने कुत्तों की नसबंदी और देखभाल के लिए 15 जुलाई को जारी किया टेंडर

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) लगता है पहली कंपनी ने अफसरों को बराबर हिस्सा नहीं दिया तो उसकी छुट्टी कर दी गई है और नई कंपनी तलाशी जा रही है। कागजों पर बड़े विकास कार्य करा करोड़ों रुपयों का घोटाला करने में माहिर नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी लूट कमाई का कोई मौका जाने नहीं देते। शहर में आवारा कुत्तों के नाम पर सरकारी खजाने में सेंध तो पहले से ही लगी हुई थी अब उस सेंधमारी का ठेका किसी अन्य कंपनी को देने की कार्रवाई चल रही है। इसके लिए बाकायदा टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

नागरिकों के लिए समस्या बने आवारा कुत्तों की आबादी पर अंकुश लगाने, उनका टीकाकरण करने और देखभाल करने का जिम्मा नगर निगम का है। नगर निगम में इसके लिए बाकायदा आवारा पशुओं को पकड़ने का दस्ता है। निगम के कामचोर अधिकारियों ने कुत्तों की देखभाल से लेकर उनकी नसबंदी कराने का जिम्मा एक एनजीओ को सौंप दिया। एनजीओ को कुत्तों की नसबंदी कराने की भी जिम्मेदारी दी गई, इसके लिए आठ सौ रुपये प्रति नसबंदी तय की गई। जिस नगर निगम के अधिकारियों के पास यह आंकड़ा नहीं है कि शहर में कितने पालतू कुत्ते हैं और कितने आवारा, उसने किस आधार पर एनजीओ को यह जिम्मेदारी सौंपी यह समझा जा सकता है। अब आवारा कुत्ते का नाम पता तो होता नहीं, इसलिए नसबंदी का फर्जी रिकॉर्ड बना कर लूट कमाई की व्यवस्था की गई। नसबंदी के अलावा कुत्तों की देखभाल के नाम पर भी लूट कमाई का इंतजाम हो गया।

वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश गोयल कहते हैं कि कार्यों को निजी हाथों में सौंपने के नाम पर नगर निगम के खजाने पर डाका डालने की कवायद की जा रही है। कुत्तों की नसबंदी का कार्य तकनीकी है इसमें पशु चिकित्सक व सर्जन शामिल हैं, उन्हें एंटी रैबीज वैक्सीन भी योग्य चिकित्सक या पशु चिकित्सा कर्मी ही लगा सकता है। जिस एनजीओ को यह काम सौंपा गया था उसके पास न तो पशु चिकित्सक व सर्जन थे और न ही पशु व्यवहार विशेषज्ञ। अनुभवहीन संस्था को काम सौंपने का ही नतीजा है कि शहर में कुत्तों के काटने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। बीके अस्पताल के आंकड़े देखें तो सामान्य दिनों में कुत्ता काटे के औसतन पचास मामले आते हैं, ब्रीडिंग सीजन के बाद यह आंकड़ा प्रतिदिन सौ से अधिक पहुंच जाता है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कुत्तों के नाम पर एनजीओ और अधिकारियों ने नगर निगम के खजाने पर डाका डाला।

सुरेश गोयल कहते हैं कि नगर निगम के पास आवारा पशुओं को पकड़ने का अमला है और सरकारी पशु चिकित्सालय में योग्य व अनुभवी पशु चिकित्सक, सर्जन और पशु व्यवहार विशेषज्ञ मौजूद हैं। मोटा वेतन पा रहे ये पशु चिकित्सक और कर्मचारी जब इसी काम के लिए रखे गए हैं तो एनजीओ को नसबंदी और देखभाल के नाम पर हजारों रुपये देने की क्या जरूरत है? सच्चाई ये है कि सरकारी पशु चिकित्सालय जिनमें हर तरह के पशुओं के इलाज की सुविधा होनी चाहिए, वह भी स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। यदि जनता से दुश्मनी न हो तो ये आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के नाम पर एनजीओ पर पैसा लुटाने के बजाय इन पशु चिकित्सालयों की दशा सुधारने में धन खर्च करें ताकि कुत्तों ही नहीं सड़क पर आवारा घूम रहे अन्य पशुओं को इलाज की सुविधा मिलेगी और दीर्घकालिक लाभ होगा।

नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी प्रभजोत कौर ने बताया कि कुत्तों की नसबंदी और उनकी देखभाल के लिए टेंडर जारी कर एनजीओ को आमंत्रित किया गया है। केवल वही एनजीओ निविदा भर सकती हैं जिनके पास आवारा कुत्तों को रखने के लिए अपनी जगह हो, पशु अस्पताल हो जिसमें उनकी नसबंदी और उपचार हो सके।

मजदूर मोर्चा ने उनसे पिछली एनजीओ द्वारा आवारा कुत्तों की नसंबदी कराने का रिकॉर्ड और उसे भुगतान की गई राशि की जानकारी मांगी तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उनसे वाट्सएप और मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, जवाब तो तब देना है जब हो।

केंद्रीय मंत्री तो बन गए लेकिन मानसिकता पार्षद वाली ही रही

किशनपाल गूजर ने मेवला महाराजपुर में हरियाणा के 'सबसे बड़े' सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) अंधा बांटे रेवड़ी, हिर-फिर अपने को दे, फरीदाबाद-पलवल लोकसभा क्षेत्र में घूम फिर कर मेवला महराजपुर, सेक्टर 28 और आसपास के इलाकों में ही विकास कार्य करा रहे केंद्रीय राज्यमंत्री किशनपाल गूजर पर ये कहावत चरितार्थ होती दिख रही है।

फरीदाबाद-पलवल क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री किशनपाल गूजर ने बीते सोमवर को मेवला महाराजपुर में सामुदायिक भवन की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि यह हरियाणा का सबसे बड़ा सामुदायिक भवन होगा। पहले इसमें 60 गुणे 40 फीट के हॉल बनाए जाने थे लेकिन उनके कहने पर इसका डिजायन बदला गया और अब इसमें 60 गुणे 120 फीट आकार के हॉल बनाए जाएंगे। यह भवन पूर्णतया वातानुकूलित होगा। पूर्णतया वातानुकूलित तो हमारा बीके अस्पताल भी है जहां न तो वातानुकूलन की न कोई मशीन चलती है न पंखा चलता है और घोर गर्मी में मरीज और उनके तीमारदार अपनी ऐसी की तैसी कराते हैं, इसी से समझा जा सकता है कि इनका वातानुकूलित भवन कैसा होगा। उन्होंने गर्व से कहा कि 2014 से पहले और आज का मेवला महाराजपुर देख लो फर्क साफ दिखाई देगा। 2014 से पहले यहां समस्याएं ही समस्याएं थीं हमने यहां सीवर, पानी की लाइन, सीमेंटेड सड़कें, अस्पताल, अंडरपास, रेलवे फाटक पर एलिवेटेड फुटओवर ब्रिज बनवाया और अब जल्द ही बारात घर का जल्द निर्माण करवा रहे है। लगे हाथ पाठक ये भी समझ लें कि सीवर लाइन ओवर फ्लो करती है, पीने का पानी पहुंचता नहीं है और अस्पताल में न स्टाफ है, न दवाई हैं और न ही उपकरण, मात्र बिल्डिंग खड़ी कर देने से अस्पताल नहीं चलता, हां इसके बनने से कमीशन जरूर मिल जाता है।

मेवला महाराजपुर में कराए गए विकास कार्यों को गिनवाते समय किशनपाल गूजर

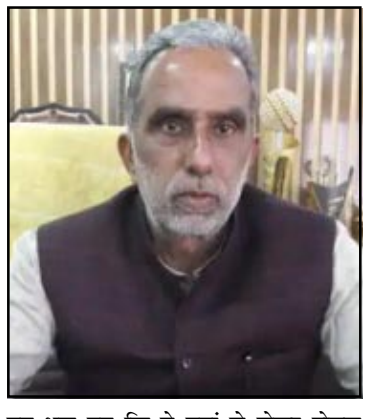

यह भूल गए कि वे यहां से लेकर होडल हथीन के भी सांसद हैं। कहने को तो वह सांसद हैं लेकिन विकास कार्य कराने में पार्षद जैसी मानसिकता से प्रेरित नजर आते हैं यानी अपने पैत्रक गांव और उसके आसपास का इलाका ही उन्हें विकास कराने के लिए नजर आता है। यहां तक कि गोद लेने के लिए उन्होंने अपने करीब का तिलपत गांव और यहीं का सरकारी स्कूल चुना। उनके संसदीय क्षेत्र के ही अन्य बहुत से गांवों में भी सामुदायिक भवन, पक्की सड़क, शुद्ध पेयजल, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अंडर पास जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं हैं।

केंद्रीय मंत्री के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस भाषण पर यहां की जनता भी उनसे दूसरे क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराने के कमेंट कर रही है। अगम सक्सेना नाम के व्यक्ति ने लिखा कि मंत्री जी मेवला अंडरपास तो बनवा दिया अब हमारे ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास की भी सुधि लीजिए सालों से इसके हाल खराब हैं। महेंद्र डागर की शिकायत थी कि बघोला में ठीकठाक हाईवे तोड़कर दोबारा क्यों बनवाया जा रहा है। नंद किशोर श्रीवास्तव ने कमेंट किया हाईवे छोड़ गलियां देखो जहां वोट मांगते रहे हो। राज शर्मा ने लिखा कि मंत्री जी 22 फीट एसजीएम नगर का बहुत बुरा हाल है कृपया ड्रेनेज सिस्टम ठीक करा दो। शत्रुजीत गुप्ता ने लिखा कि फरीदाबाद का ड्रेनेज सिस्टम कभी भी ठीक नहीं कराते सिर्फ वायदे ही वायदे। मनोज यादव ने पूछा कि मंत्री जी सेहतपुर का चेतन मार्केट रोड कब बनवा रहे हो चार बार तो उद्घाटन कर गए हो आप। शरताज तंवर लिखते हैं कि पियाला गांव की रोड के पैसे तो तुम खा गए। लकपत अली ने पूछा कि कैल गांव की सड़क कब बनाई जाएगी। ये सभी समस्याएं केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर के संसदीय क्षेत्र की ही हैं। वह बीते नौ साल से न केवल सांसद हैं बल्कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, ऐसे में जब वह 2014 से पहले के मेवला महाराजपुर की बात करते हैं तो उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के बाकी पिछड़े, मूलभूत सुविधाओं और विकास से दूर के शहरी और ग्रामीण इलाकों को भी ध्यान में रखना चाहिए।